भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 498

09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

योग को बढ़ावा देना

498. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:
श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले':
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री राम कृपाल यादव:
डॉ. अमर सिंह:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री संजय काका पाटील:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री अजय कुमार मंडल:
श्रीमती रीती पाठक:
श्रीमती रमा देवी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए नए योग प्रशिक्षण केंद्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का योग को बढ़ावा देने के लिए योग प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने और इससे संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नए योग केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ इसके लिए देश में योग प्रशिक्षकों तथा अवसंरचना की व्यवस्था करने का विचार है और यदि हां, तो महाराष्ट्र और गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ग्रामीण लोगों के लिए गावों में योग प्रशिक्षकों/व्यायाम प्रशिक्षकों के प्रावधान करने और आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित ओपन जिम स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का योग के माध्यम से असावधानी, अति सक्रियता और आवेगशीलता जैसे मुख्य लक्षणों में सुधार करके अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) वाले बच्चों की मदद करने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित योग प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है और आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए नए योग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

आयुष मंत्रालय अपने तीन स्वायत्त निकायों नामत: मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे के माध्यम से देश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है। एमडीएनआईवाई योग शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सीसीआरवाईएन, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान और विकास के लिए शीर्ष निकाय है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए प्रमुख संस्थान एनआईएन, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है।

एमडीएनआईवाई, सीसीआरवाईएन और एनआईएन की गतिविधियां और कार्यक्रम क्रमशः yogamdniy.nic.in, www.ccryn.gov.in और ninpune.ayush.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने योग पेशेवरों के प्रमाणन और विभिन्न श्रेणियों के तहत संस्थानों के प्रत्यायन के लिए एक योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी) की स्थापना की है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आयुष मंत्रालय हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) आयोजित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। आईडीवाई का आयोजन सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी), जो योग पोर्टल (yoga.ayush.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, पर आधारित एक सामूहिक योग प्रदर्शन पर केंद्रित है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में योग सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, एनएएम दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) का संचालन कर रहा है। इन आयुष एचडब्ल्यूसी में, योग्य योग प्रशिक्षकों द्वारा लोगों को सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समुदाय-आधारित उपचार के रूप में योग सिखाया जाएगा।

(घ) और (ङ): मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****